Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

18 जून 2025

NATIONAL AFFAIRS / GOVERNMENT SCHEME

1. बिहार ने शहरी चुनावों के लिए भारत की पहली मोबाइल-आधारित ई-वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की।

डिजिटल लोकतंत्र की ओर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भारत की पहली मोबाइल-आधारित ई-वोटिंग प्रणाली शुरू की है, जिससे मतदाता सीधे स्मार्टफोन के माध्यम से अपने मत डाल सकेंगे।

- **नई प्रणाली प्रवासी श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को एक सुरक्षित मोबाइल ऐप का उपयोग करके घर से मतदान करने में सक्षम बनाती है - विशेष रूप से उन लोगों को लाभ होगा जिन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई होती है।**

- **पात्र मतदाता 22 जून 2025 तक एक समर्पित ऐप के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। मतदान के दिन, वे एक ओटीपी के साथ अपनी पहचान सत्यापित करते हैं, और वोट को अंतिम रूप देने से पहले ऐप में VVPAT -(वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) जैसी एक पुष्टिकरण स्क्रीन होती है।**

- **यह प्लेटफॉर्म छेड़छाड़-रोधी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण (OTP) और ब्लॉकचेन एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, ECI का ECINET डैशबोर्ड डेटा अखंडता की देखरेख करेगा, रोल अपडेट को सुव्यवस्थित करेगा और मतदान को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करेगा।**

Key Points:-

(i) मोबाइल ई-वोटिंग सिस्टम का प्रयोग 28 जून को छह नगर निकायों में होने वाले चुनावों के दौरान किया जाएगा। इसमें एक डिवाइस पर दो मतदाताओं को अनुमति दी जाएगी, जिससे लचीलापन बढ़ेगा और नियंत्रित पहुंच सुनिश्चित होगी।

(ii) गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा स्थापित की जाएगी, जिसका प्रबंधन चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। मतदाता अपना वोट डालने के बाद अपने डिवाइस वापस ले सकते हैं।

(iii) यह पहल डिजिटल इंडिया प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और नगर निकाय चुनावों में दूरस्थ मतदान (remote voting) की दिशा में एक मिसाल स्थापित करती है। यह निर्वाचन आयोग (ECI) की व्यापक आधुनिकीकरण योजनाओं—जैसे M3 EVMs, VVPATs और ECINET—के साथ मेल खाती है, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता और मतदाता सुलभता को बढ़ाना है।

2. मारुति सुजुकी ने मानेसर में भारत के सबसे बड़े इन-प्लांट रेल लॉजिस्टिक्स हब का उद्घाटन किया।

हरित गतिशीलता और औद्योगिक रसद सुधार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने हरियाणा के मानेसर में अपने विनिर्माण संयंत्र में

देश की सबसे बड़ी इन-प्लांट रेलवे साइडिंग शुरू की है। यह परियोजना PM GatiShakti के तहत भारत के दीर्घकालिक बुनियादी ढाँचे के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो रेल द्वारा उच्च दक्षता वाली माल ढुलाई के माध्यम से सड़क यातायात, कार्बन उत्सर्जन और रसद लागत को कम करने का वादा करती है।

• यह नई साइडिंग हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से जुड़ी है, जो पलवल और सोनीपत के बीच फैली एक समर्पित औद्योगिक रेल लाइन है। मारुति का आंतरिक नेटवर्क 6.9 किलोमीटर के रास्ते उत्तरी रेलवे के पाटली स्टेशन से जुड़ता है, जिससे भारत के व्यापक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के साथ सहज एकीकरण संभव हो पाता है।

• 8.2 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक लंबाई के साथ 46 एकड़ में फैली यह सुविधा प्रति वर्ष लगभग 4.5 लाख वाहनों की डिस्पैच को संभाल सकती है। सालाना लगभग 65,000 ट्रक ट्रिप को बदलकर, यह अनुमान लगाया गया है कि इससे 1.75 लाख टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी और 60 मिलियन लीटर तक डीज़ल की बचत होगी, जिससे मारुति के लॉजिस्टिक्स संचालन के कार्बन फ़ुटप्रिंट में काफ़ी कमी आएगी।

• उद्घाटन माल ढुलाई अभियान में 276 वाहनों को लेकर एक रेक मानेसर सुविधा से नागपुर के लिए रवाना हुआ। इसने मारुति सुजुकी के लिए एक नए लॉजिस्टिक्स युग की शुरुआत की, जिसमें मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन पर जोर दिया गया।

Key Points:-

(i) मारुति सुज़ुकी ने कुल मिलाकर लगभग ₹454 करोड़ का निवेश किया है - ₹327 करोड़ रेल कॉरिडोर के लिए और ₹127 करोड़ यार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यह पहल उत्तर भारत में मल्टीमॉडल एकीकरण में सुधार और औद्योगिक रसद में तेजी लाकर सीधे पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का समर्थन करती है।

(ii) वर्तमान में मारुति के लगभग 24% तैयार वाहन रेल के माध्यम से परिवहन किए जाते हैं। इस सुविधा के जुड़ने के साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2029-30 तक इसे 35% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने गुजरात प्लांट में अपनी पिछली सफलता से प्रेरणा लेते हुए यह लक्ष्य रखा है, जिसने देश के पहले इन-प्लांट रेलवे टर्मिनल का बीड़ा उठाया था।

(iii) मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और सीईओ हिसाशी टेकाउची ने इस बात पर जोर दिया कि यह परियोजना स्थिरता, लागत-दक्षता और भारत के जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखण के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उम्मीद है कि यह साइडिंग शुद्ध-शून्य उत्सर्जन और कम आपूर्ति श्रृंखला संचालन को प्राप्त करने की दिशा में मारुति के रोडमैप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

3. भारत के ICAR-NIHSAD भोपाल को WOAH-FAO द्वारा रिंडरपेस्ट वायरस नियंत्रण के लिए श्रेणी 'A' का दर्जा प्राप्त हुआ।

भारत ने वैश्विक पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जहां भोपाल, मध्य प्रदेश स्थित ICAR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिज़ीज़ेज़ (ICAR-NIHSAD) को कैटेगरी 'A' रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी (RHF) के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यह मान्यता पेरिस स्थित वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ (WOAH) और संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (FAO) द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की गई है।

• यह घोषणा पेरिस में 25-29 मई, 2025 को आयोजित WOAH के 92वें आम सत्र के दौरान की गई। इस वैश्विक मंच ने अत्यधिक संवेदनशील रिंडरपेस्ट वायरस युक्त सामग्रियों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने की भारत की क्षमता को मान्यता दी, एक ऐसा वायरस जिसे आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है लेकिन आपातकालीन तैयारियों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसे बरकरार रखा गया है।

• मान्यता प्रमाणपत्र मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MoFAHD) के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) की सचिव अलका उपाध्याय को प्रदान किया गया। समारोह की अध्यक्षता WOAH के महानिदेशक डॉ. इमैनुएल सौबेरन और WOAH की अध्यक्ष डॉ. सुज़ाना पोम्बो ने की।

• इस श्रेणी ए दर्जे के साथ, ICAR-NIHSAD को सख्त वैश्विक जैव सुरक्षा दिशा-निर्देशों के तहत वैक्सीन स्टॉक सहित सभी प्रकार की रिंडरपेस्ट वायरस सामग्रियों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत, निगरानी और संभालने का अधिकार है। यह पशु चिकित्सा विषाणु विज्ञान और प्रकोप की तैयारी में भारत की तकनीकी क्षमताओं की पुष्टि करता है।

Key Points:-

(i) यह उपलब्धि भारत को उन चुनिंदा छह अधिकृत वैश्विक केंद्रों के समूह में शामिल करती है, जिन्हें रिंडरपेस्ट वायरस सामग्री (RVCM) के उच्च-सुरक्षा भंडारण का काम सौंपा गया है। ये सुविधाएं भविष्य में आपातकालीन वैक्सीन उत्पादन या वायरल विश्लेषण की किसी भी आवश्यकता के मामले में महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में काम करती हैं।

(ii) NISHAD को श्रेणी A में शामिल करने से वैश्विक पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैव सुरक्षा में अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।

(iii) यह अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और रोग नियंत्रण संस्थानों के साथ सहयोग के नए रास्ते भी खोलता है।

4. भारत ने बढ़ते इजरायल-ईरान तनाव के बीच ईरान से 110 छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया।

ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच, भारत सरकार ने हाल ही में 18 जून, 2025 को 'ऑपरेशन सिंधु' शुरू किया है, ताकि ईरान के संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों-विशेष रूप से मेडिकल छात्रों-को सुरक्षित निकाला जा सके। यह ऑपरेशन विदेश में नागरिकों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भारत के नवीनतम मानवीय प्रयास को दर्शाता है, जो इसकी सक्रिय विदेश नीति को मजबूत करता है।

• ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत 13 जून, 2025 को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले के बाद हुई थी, जो ईरान समर्थित छद्म गतिविधियों के जवाब में किया गया था। इन हमलों ने ईरान में सैन्य संघर्ष को और तेज़ कर दिया, जिसके कारण मिसाइलों का प्रक्षेपण, इंटरनेट बंद होना, बिजली गुल होना और नागरिक व्यवधान उत्पन्न हुए, खासकर तेहरान, तबरीज़ और उर्मिया जैसे शहरी केंद्रों में - जहाँ सैकड़ों भारतीय मेडिकल छात्र पढ़ते हैं।

• 18 जून को विदेश मंत्रालय (MEA) ने ऑपरेशन सिंधु के पहले चरण को सक्रिय किया, जिसमें उत्तर-पश्चिमी ईरान के उर्मिया से 110 भारतीय छात्रों को सफलतापूर्वक निकाला गया। छात्रों को ज़मीन के रास्ते येरेवन, आर्मेनिया ले जाया गया और फिर एक विशेष निकासी विमान के

ज़रिए नई दिल्ली लाया गया, जो 19 जून की सुबह सुरक्षित रूप से उतरा।

• इस निकासी का समन्वय तेहरान और येरेवन में भारतीय दूतावासों द्वारा अर्मेनियाई सरकार के साथ साझेदारी में किया गया। राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मिशन की निगरानी की, जबकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुष्टि की कि ईरान में अभी भी मौजूद छात्रों के लिए तुर्कमेनिस्तान और जॉर्जिया के माध्यम से अतिरिक्त निकासी की व्यवस्था की जा रही है।

Key Points:-

(i) ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन, 2022) और ऑपरेशन कावेरी (सूडान, 2023) जैसे पिछले भारतीय प्रयासों की याद दिलाता है। यह भारत की कूटनीतिक चपलता और उच्च जोखिम वाले भू-राजनीतिक क्षेत्रों में भी अपने प्रवासी समुदाय की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की प्रतिष्ठा को पुष्ट करता है।

(ii) ईरान में 4,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक, जिनमें ज़्यादातर छात्र हैं, अभी भी मौजूद हैं। भारत सरकार ने चल रहे निकासी अभियान को प्रबंधित करने के लिए दूतावासों में 24x7 हेल्पलाइन और शिकायत प्रकोष्ठ सक्रिय किए हैं।

(iii) अतिरिक्त उड़ानों की योजना बनाई जा रही है, जिसमें सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की योजना है। यह अभियान तब तक चरणों में जारी रहेगा जब तक कि सभी संकटग्रस्त भारतीयों को सुरक्षित घर नहीं लाया जाता।

INTERNATIONAL

1. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया।

2 मई, 2024 को अपनाए गए एक ऐतिहासिक संकल्प में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने आधिकारिक तौर पर संकल्प A/RES/78/279 के माध्यम से 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष (IYWF) के रूप में घोषित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित और 123 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सह-प्रायोजित, यह घोषणा कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण लेकिन ऐतिहासिक रूप से कम पहचानी गई भूमिका को मान्यता देती है और इसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में लैंगिक असमानताओं को दूर करना है।

• अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष कृषि में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करेगा, विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां वे 60-80% खाद्य उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं और वैश्विक कृषि कार्यबल का लगभग 39% प्रतिनिधित्व करती हैं।

• उनके योगदान के बावजूद, विश्व स्तर पर महिलाओं के पास 15% से भी कम कृषि भूमि है, उन्हें ऋण, बाजार, मशीनीकरण तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है, तथा अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें कानूनी अधिकारों या सामाजिक सुरक्षा का भी अभाव होता है।

• UNGA प्रस्ताव में कहा गया है कि खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) रोम स्थित एजेंसियों जैसे IFAD (अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष) और WFP(विश्व खाद्य कार्यक्रम) के साथ मिलकर भूमि स्वामित्व, वित्तीय समावेशन, जलवायु अनुकूलन और निर्णय लेने की शक्ति में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए IYWF 2026 के दौरान

वैश्विक प्रयासों का समन्वय करेगा। यह वर्ष कृषि में महिलाओं की आवाज़ को भी बढ़ाएगा, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा और खाद्य प्रणाली में लैंगिक-परिवर्तनकारी नीतियों की वकालत करेगा।

Key Points:-

(i) घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का दृढ़ता से समर्थन करता है, विशेष रूप से SDG 2 (भूख से मुक्ति) और SDG 5 (लैंगिक समानता)। इसमें समावेशी कृषि परिवर्तन का आह्वान किया गया है, जिसमें सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र से लिंग-संवेदनशील नीतियों को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण, सिंचाई और प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले कृषि व्यवसाय मॉडल में निवेश करने का आग्रह किया गया है।

(ii) यह पहल वैश्विक कृषि सुधार में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो यह स्वीकार करता है कि महिला किसानों को सशक्त बनाने से न केवल समानता का समर्थन होता है, बल्कि बड़े पैमाने पर पैदावार, खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी सुधार होता है। एफएओ के अध्ययनों से पता चलता है कि कृषि में लैंगिक अंतर को कम करने से विकासशील देशों में उत्पादन में 4% तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे वैश्विक स्तर पर कुपोषित लोगों की संख्या में 100-150 मिलियन की कमी आ सकती है।

(iii) वर्ष 2026 को अब आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तथा संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्य देशों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, सहकारी समितियों और महिला-नेतृत्व वाले ग्रामीण आंदोलनों को लिंग-समान कृषि विकास को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे अधिक समावेशी, लचीली और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों की नींव रखी जा सके।

2. भारत ने जिनेवा में 113वें ILO सम्मेलन में ऐतिहासिक श्रम सुधार और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रस्तुत किए।

2-13 जून 2025 तक, भारत ने जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित 113वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (ILC) में सक्रिय रूप से भाग लिया, जहां इसने अपने व्यापक श्रम संहिता सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कवरेज में नाटकीय वृद्धि पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया।

- **भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया (श्रम एवं रोजगार) ने किया, जिसमें राज्य मंत्री, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और नियोक्ता तथा श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस मजबूत उपस्थिति ने वैश्विक श्रम मानकों को आकार देने में भारत की सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया।**

- **भारत ने 29 पुराने श्रम कानूनों को चार आधुनिक संहिताओं में सफलतापूर्वक समाहित कर दिखाया है - जिसमें मजदूरी, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं। इन सुधारों का उद्देश्य अनुपालन को सुव्यवस्थित करना, श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ाना और श्रम बाजार को औपचारिक बनाना है।**

- **नए ILO डेटा का हवाला देते हुए, मंत्री मंडाविया ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में नाटकीय वृद्धि पर प्रकाश डाला, जो 2015 में सिर्फ 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है - अब लगभग 940 मिलियन भारतीयों को कवर किया जा रहा है, जिससे भारत कवरेज के मामले में विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।**

Key Points:-

(i) मंडाविया ने यह भी बताया कि भारत की बेरोजगारी दर 2017 में ~6% से घटकर 2024 में 3.2% हो गई है, साथ ही 75 मिलियन से अधिक औपचारिक क्षेत्र की नौकरियाँ सृजित हुई हैं। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना - जिसका बजट 12.8 बिलियन अमरीकी डॉलर है - से रोजगार को और बढ़ावा मिलने और अनौपचारिक से औपचारिक काम में बदलाव को सुगम बनाने की उम्मीद है।

(ii) उभरते श्रम गतिशीलता पर विचार करते हुए, भारत ने गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसके 2030 तक 23.5 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ई-श्रम पोर्टल, जिसमें अब 300 मिलियन से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हैं, को लक्षित सामाजिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उजागर किया गया।

(iii) ILC पूर्ण अधिवेशन और अन्य कार्यक्रमों के दौरान भारत ने कार्यस्थल पर जैविक खतरों और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में सभ्य कार्य पर नए अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास का समर्थन किया। प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक मानदंडों के संदर्भ-संवेदनशील कार्यान्वयन पर भी जोर दिया, खासकर MSMEs और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए।

3. OpenAI को अमेरिकी रक्षा विभाग से मिला 200 मिलियन डॉलर का AI कॉन्ट्रैक्ट।

OpenAI को हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग (U.S. Department of Defense) द्वारा 200 मिलियन डॉलर (लगभग ₹1,670 करोड़) का अनुबंध प्राप्त हुआ है। यह अनुबंध एडवांस्ड एआई सिस्टम विकसित करने के लिए दिया गया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, और सरकारी सेवाओं में उपयोग किए जाएंगे। यह OpenAI का अमेरिकी सैन्य क्षेत्र में पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है।

- **यह एक पायलट कार्यक्रम है जो जुलाई 2026 तक चलेगा। इसका संचालन वाशिंगटन डी.सी. में किया जाएगा। इसमें OpenAI हेल्थकेयर, रक्षा रणनीति, साइबर सुरक्षा, और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में AI समाधान तैयार करेगा।**

- **यह एक पायलट कार्यक्रम है जो जुलाई 2026 तक चलेगा। इसका संचालन वाशिंगटन डी.सी. में किया जाएगा। इसमें OpenAI हेल्थकेयर, रक्षा रणनीति, साइबर सुरक्षा, और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में AI समाधान तैयार करेगा।**

- **इस अनुबंध के साथ ही OpenAI ने 'OpenAI for Government' नामक एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए खास AI मॉडल्स — जैसे ChatGPT Enterprise और ChatGPT Gov — तैयार किए जाएंगे।**

Key Points:-

(i) इस अनुबंध के लिए कुल 12 कंपनियों ने आवेदन किया था। इस जीत से OpenAI अब पारंपरिक रक्षा सॉफ्टवेयर कंपनियों — जैसे Palantir — को चुनौती देने की स्थिति में आ गया है।

(ii) OpenAI इससे पहले भी रक्षा स्टार्टअप Anduril के साथ साझेदारी कर चुका है, जहां इसके AI मॉडल्स का उपयोग एंटी-ड्रोन सिस्टम्स में हुआ था। CEO सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में $500 बिलियन के "Stargate" AI इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन का समर्थन भी किया है।

(iii) हालांकि यह अनुबंध रक्षा मंत्रालय के साथ है, OpenAI

ने साफ किया है कि उसके एआई मॉडल्स का उपयोग हथियार बनाने, हानिकारक कार्यों या सैन्य हमलों में नहीं होगा। अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी पुष्टि की है कि अनुबंध के तहत सभी प्रयोग नैतिक दिशानिर्देशों के अंतर्गत होंगे।

4. वियतनाम BRICS में 10वें साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ, जिससे वैश्विक दक्षिण सहयोग गहरा हुआ।

13 जून, 2025 को, वर्तमान में BRICS की अध्यक्षता कर रही ब्राज़ील सरकार ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वियतनाम उसका 10वाँ "भागीदार देश" है। यह दर्जा वियतनाम को पूर्ण सदस्यता के बिना BRICS शिखर सम्मेलनों और बैठकों में भाग लेने की अनुमति देता है, जो दक्षिण-दक्षिण एकजुटता और सतत विकास में इसके बढ़ते महत्व को उजागर करता है।

• BRICS ने व्यापक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 2024 में भागीदार देश श्रेणी की शुरुआत की। भागीदार के रूप में, वियतनाम बैठकों में भाग ले सकता है, घोषणाओं का समर्थन कर सकता है, और पूर्ण सदस्यता दायित्वों से बंधे बिना प्रमुख परियोजनाओं पर सहयोग कर सकता है।

• वियतनाम नौ मौजूदा साझेदारों के विविध समूह में शामिल हो गया है, जिसमें बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान शामिल हैं - जिससे यह यह दर्जा प्राप्त करने वाला 10वां देश बन गया है।

• 2025 BRICS प्रेसीडेंसी के मेज़बान के रूप में बोलते हुए ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय ने वियतनाम के प्रवेश का समर्थन किया। बयान में दक्षिण-दक्षिण सहयोग में वियतनाम की भूमिका और सतत विकास के लिए उसके दृढ़ प्रयास पर ज़ोर दिया गया, तथा उसे एक मूल्यवान एशियाई साझेदार के रूप में पेश किया गया।

Key Points:-

(i) वियतनाम का शामिल होना उसकी "बांस कूटनीति" की कूटनीतिक रणनीति को दर्शाता है - रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए प्रमुख शक्तियों के साथ साझेदारी को संतुलित करना। यह ASEAN (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संघ), APEC (एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग), जी7/जी20 (सात का समूह/बीस का समूह) और OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) सहित वैश्विक मंचों पर हनोई के प्रभाव को बढ़ाता है।

(ii) BRICS साझेदार श्रेणी में सदस्यता वियतनाम को न्यू डेवलपमेंट बैंक और संयुक्त अवसंरचना/निवेश पहलों के साथ और अधिक निकटता से जोड़ती है, जो व्यापार साझेदारी में विविधता लाने और बहुपक्षीय संपर्क बढ़ाने की इसकी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है।

(iii) हालांकि वियतनाम ने पहले ही BRICS में गहन भागीदारी में रुचि दिखाई थी - जिसका प्रमाण उसके नेता की BRICS + में भागीदारी है - लेकिन हनोई अमेरिका सहित पश्चिमी साझेदारों के साथ रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए पूर्ण सदस्यता के बारे में सतर्क है।

BANKING & FINANCE

1. RBI ने सरकारी लेनदेन संभालने वाले बैंकों के लिए एजेंसी कमीशन बढ़ाया।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकारी लेनदेन के प्रसंस्करण में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाले बैंकों के लिए एजेंसी कमीशन दरों को बढ़ाने के लिए RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45 के तहत 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी एक संशोधित मास्टर परिपत्र (RBI/2025-26/06) जारी किया है।

• यह परिपत्र 31 मार्च, 2025 तक जारी किए गए निर्देशों को समेकित करता है, और राजस्व संग्रह, सरकारी भुगतान, पेंशन संवितरण और लघु बचत योजना (SSS) संचालन जैसे आवश्यक कार्यों को संभालने के लिए एजेंसी बैंकों को पारिश्रमिक देने के RBI के आदेश को दोहराता है - जिसमें सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि और किसान विकास पत्र शामिल हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा SSS के लिए कमीशन वहन किया जाता है।

• नए सर्कुलर के तहत, अपडेट की गई कमीशन दरें इस प्रकार हैं: ₹40 प्रति भौतिक रसीद, ₹12 प्रति इलेक्ट्रॉनिक रसीद, और पर्याप्त ₹80 प्रति पेंशन भुगतान। इसके अतिरिक्त, बैंकों को अब अन्य सभी पात्र भुगतान लेनदेन के लिए प्रति ₹100 टर्नओवर पर 7 पैसे मिलेंगे, सिवाय उन प्री-फंडेड योजनाओं या लेनदेन के जहां सरकारी एजेंसियों द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाता है।

• परिपत्र में स्पष्ट रूप से अयोग्य लेनदेन की श्रेणियों को रेखांकित किया गया है - जैसे बैंक गारंटी, वैधानिक/स्वायत्त निकायों के साथ लेनदेन, पूंजी भुगतान, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना लेनदेन, और वित्तीय संस्थानों से ऋण या निकासी - जो एजेंसी कमीशन के लिए योग्य नहीं होंगे।

Key Points:-

(i) अपने कमीशन का दावा करने के लिए, एजेंसी बैंकों को प्रतिदिन शाम 6 बजे से पहले QPX/e-Kuber के माध्यम से लेनदेन रिपोर्ट अपलोड करनी होगी और केंद्रीय लेखा अनुभाग (CAS), नागपुर या संबंधित क्षेत्रीय RBI कार्यालयों में तिमाही दावे प्रस्तुत करने होंगे। बैंकों को यह भी प्रमाणित करना होगा कि दावा किए गए लेनदेन में से कोई भी अयोग्य नहीं है।

(ii) सही दावा प्रक्रियाओं का पालन न करने पर बैंक दर के साथ 2% अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज लगाया जा सकता है।

(iii) कुल मिलाकर, एजेंसी कमीशन दरों में वृद्धि और स्पष्ट पात्रता मानदंड, उन्नत रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल और दंड प्रावधानों को औपचारिक रूप देकर, RBI का लक्ष्य महत्वपूर्ण सरकारी व्यवसाय करने वाले बैंकों के लिए प्रक्रियात्मक दक्षता, पारदर्शिता और उचित पारिश्रमिक को मजबूत करना है - विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत के लिए प्रबंध निदेशक और प्रमुख नियुक्त किया।

एक रणनीतिक नेतृत्व कदम में, कैलिफोर्निया, USA में मुख्यालय वाली मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने 1 जुलाई, 2025 से

अरुण श्रीनिवास को मेटा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक (MD) और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। यह परिवर्तन, अपने सबसे बड़े विकास बाजारों में से एक में नेतृत्व को सुदृढ़ करने के लिए मेटा की व्यापक योजना का हिस्सा है, भारत के MD की भूमिका से संध्या देवनाथन के बाहर निकलने के बाद, क्योंकि वह अब भारत और दक्षिण पूर्व एशिया (SEA) में कंपनी के संचालन का नेतृत्व करती हैं।

- **अरुण श्रीनिवास संध्या देवनाथन की जगह लेंगे, जिन्होंने अब एक बड़ी क्षेत्रीय भूमिका संभाली है। श्रीनिवास मेटा की भारत रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें व्यापार वृद्धि, नवाचार, विज्ञापनदाता जुड़ाव और राजस्व विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वह भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए मेटा की उपाध्यक्ष संध्या देवनाथन को सीधे रिपोर्ट करना जारी रखेंगे।**

- **अरुण श्रीनिवास अपने साथ बिक्री, विपणन और डिजिटल रणनीति के क्षेत्र में लगभग तीन दशकों का अनुभव लेकर आए हैं। उन्होंने 1996 में रीबॉक में अपना कॉर्पोरेट करियर शुरू किया और बाद में 2017 तक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) में कई प्रमुख पदों पर काम किया, अंततः मुंबई में स्थित VP - फूड्स साउथ एशिया बन गए।**

- **मेटा में शामिल होने से पहले, उन्होंने वेस्टब्रिज कैपिटल (2017-2019) में ऑपरेटिंग सलाहकार के रूप में काम किया, और फिर 2019 से 2020 तक ओला में मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) और वैश्विक मुख्य विपणन अधिकारी (CMO) की दोहरी भूमिका निभाई, भारत और विदेशों में व्यापार विस्तार और ग्राहक जुड़ाव रणनीतियों की देखरेख की।**

Key Points:-

(i) सितंबर 2020 में भारत के लिए विज्ञापन व्यवसाय के निदेशक और प्रमुख के रूप में मेटा में शामिल होने के बाद से, अरुण श्रीनिवास ने कंपनी की मुद्रीकरण रणनीति का नेतृत्व किया, जिसमें विज्ञापन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने और AI टूल और क्षेत्रीय आउटरीच का उपयोग करके फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर विज्ञापनदाता का विश्वास बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

(ii) यह नेतृत्व परिवर्तन ऐसे समय में हुआ है जब मेटा भारत में विनियामक चुनौतियों और डेटा गवर्नेंस के मुद्दों को संबोधित कर रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की बढ़ती जांच और व्हाट्सएप के डेटा-शेयरिंग ढांचे पर चिंताओं के साथ, विकास और अनुपालन को बनाए रखने के लिए एक मजबूत और अनुभवी नेता का होना महत्वपूर्ण है।

(iii) भारत मेटा के लिए एक प्रमुख बाजार बना हुआ है, जहाँ बिजनेस मैसेजिंग, रील्स, क्रिएटर इकॉनमी और एआई इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। अरुण श्रीनिवास के नेतृत्व में, मेटा का लक्ष्य विज्ञापनदाता संबंधों को गहरा करना, क्षेत्रीय कंटेंट क्रिएटर्स में निवेश करना और मेटा प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से छोटे व्यवसाय की सहभागिता को बढ़ाना है।

SPORTS

1. ICC 2027-29 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में छोटे देशों के लिए 4 दिवसीय टेस्ट की अनुमति देगा।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) 2027-29 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है: उभरते क्रिकेट देशों के लिए चार दिवसीय टेस्ट मैचों की अनुमति देना। इस बदलाव का उद्देश्य छोटे बोर्डों के लिए टेस्ट क्रिकेट को अधिक व्यवहार्य बनाना है, जबकि

पारंपरिक पाँच दिवसीय मैच मार्की प्रतिद्वंद्विता के लिए बने रहेंगे।

• छोटे क्रिकेट खेलने वाले देशों को पांच दिवसीय टेस्ट मैचों की मेज़बानी करने में तार्किक और वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मैच की अवधि कम करके, बोर्ड तीन हफ़्तों से कम समय में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ की मेज़बानी कर सकते हैं, जिससे खेलने के अवसर बढ़ेंगे और टेस्ट फ़ॉर्मेट को ज़्यादा व्यापक रूप से फैलाने में मदद मिलेगी।

• ICC के अध्यक्ष जय शाह ने लॉर्ड्स में WTC फाइनल में चर्चा के दौरान इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि यह योजना 2027-29 चक्र के लिए तैयार हो सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एशेज, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी और एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी जैसी प्रमुख सीरीज पांच दिवसीय ही रहेंगी।

• प्रतिस्पर्धात्मक अखंडता बनाए रखने के लिए, चार दिवसीय टेस्ट मैचों में प्रति दिन न्यूनतम 98 ओवर होंगे, जबकि पांच दिवसीय मैचों में मानक 90 ओवर होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कम अवधि के कारण खेल का स्तर कम न हो।

Key Points:-

(i) ICC ने इससे पहले 2017 में द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के लिए चार दिवसीय टेस्ट को मंजूरी दी थी, जिसमें आयरलैंड, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के मैच शामिल थे। लेकिन इसे WTC पर लागू करना पहला बड़ा वैश्विक प्रारूप परिवर्तन होगा।

(ii) श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड जैसे देश अक्सर लंबी सीरीज आयोजित करने में संघर्ष करते हैं। चार दिवसीय प्रारूप उन्हें अधिक अवसर प्रदान करेगा, जिससे दक्षिण अफ्रीका द्वारा उनके विरल टेस्ट कैलेंडर पर व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान होगा, जबकि वे वर्तमान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन हैं।

(iii) ICC 2027-29 WTC चक्र के लिए चार दिवसीय टेस्ट मैचों के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है, जबकि 2025-27 की अवधि के लिए पांच दिवसीय टेस्ट को बरकरार रखा जाएगा। सदस्य बोर्डों और हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद इस कदम का उद्देश्य छोटे देशों के लिए समावेशिता और वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाना है, बिना मार्की पांच दिवसीय प्रतिद्वंद्विता को प्रभावित किए।

2. ICC ने भारत और श्रीलंका में 2025 में होने वाले महिला वनडे विश्व कप का कार्यक्रम घोषित किया।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 13वें महिला वनडे विश्व कप के पूर्ण कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से अनावरण किया है, जो 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक चलेगा। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे, जिसमें आठ शीर्ष टीमें, पांच आयोजन स्थल शामिल होंगे, जिसमें पाकिस्तान के मैचों के लिए एक अद्वितीय हाइब्रिड मॉडल भी शामिल है।

• आठ देश - भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश - एकल राउंड-रॉबिन ग्रुप चरण में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसके बाद शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचेंगी, कुल 31 मैच होंगे।

• टूर्नामेंट की शुरुआत 30 सितंबर को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में भारत बनाम श्रीलंका के साथ होगी। दो सेमीफाइनल 29-30 अक्टूबर (गुवाहाटी या कोलंबो और बेंगलुरु) के लिए निर्धारित हैं, और 2 नवंबर को होने वाला

फाइनल पाकिस्तान की प्रगति के आधार पर बेंगलुरु या कोलंबो में से किसी एक में आयोजित किया जाएगा।

• भारतीय स्थलों में बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर (होलकर स्टेडियम) और विशाखापत्तनम शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के सभी लीग मैच हाइब्रिड होस्टिंग मॉडल के तहत कोलंबो के आर.प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे।

Key Points:-

(i) बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान मैच 5 अक्टूबर 2025 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में, चल रहे क्षेत्रीय तनावों के बीच, ICC के हाइब्रिड मॉडल समझौते के अनुसार एक तटस्थ स्थल पर खेला जाएगा।

(ii) होलकर स्टेडियम, इंदौर, पांच मैचों की मेजबानी करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूज़ीलैंड (1 अक्टूबर), भारत बनाम इंग्लैंड (19 अक्टूबर), ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (22 अक्टूबर), और ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (25 अक्टूबर) जैसे बड़े मुकाबले शामिल हैं - जो 28 साल बाद महिला क्रिकेट की वापसी को चिह्नित करेंगे।

(iii) यह भारत में चौथा महिला वनडे विश्व कप है (पिछली जीत 1978, 1997, 2013 में हुई थी) और श्रीलंका में पहला, जो केवल आठ टीमों के साथ अंतिम संस्करण है। ICC को उम्मीद है कि महिला क्रिकेट में वैश्विक विकास का समर्थन करने के लिए भविष्य के टूर्नामेंटों में विस्तार किया जाएगा।

3. भारत की टीम MGD1 ने लंदन में 2025 फिडे विश्व रैपिड टीम चैम्पियनशिप जीती।

11-13 जून को लंदन में आयोजित FIDE वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप 2025 में, भारत की टीम MGD1 (टीम MGD1 एक शतरंज टीम है) ने रैपिड टीम खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनकर इतिहास रच दिया। 12 राउंड के स्विस प्रारूप में 52 अंतरराष्ट्रीय टीमों को मात देते हुए, उन्होंने संभावित 24 में से 21 मैच पॉइंट के साथ शीर्ष सम्मान हासिल किया।

• दुनिया भर की 50 से ज़्यादा टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा करते हुए, टीम MGD1 ने 10 मैच जीते, 1 ड्रॉ रहा और सिर्फ़ 1 मैच हारा, और 21 मैच पॉइंट के साथ समाप्त हुआ। उनके प्रदर्शन में निरंतरता और लचीलापन झलकता है।

• अंतिम दिन, टीम MGD1 ने शानदार प्रदर्शन किया - सभी 4 मैच जीतते हुए - हेक्सामाइंड शतरंज टीम जैसे प्रतिद्वंद्वियों को हराया, जिन्होंने 20 मैच प्वाइंट जुटाए।

• टीम में अर्जुन एरिगैसी, पेंटाला हरिकृष्णा, लियोन ल्यूक मेंडोंका, प्रणव वेंकटेश जैसे शीर्ष भारतीय ग्रैंडमास्टर्स के साथ-साथ शौकिया बोर्ड खिलाड़ी अथर्व पी तायडे भी शामिल थे, जिनके उल्लेखनीय 11/12 स्कोर ने टीम के प्रयास को काफी बढ़ावा दिया।

Key Points:-

(i) उनकी जीत अंतिम दौर में UK स्थित मैल्कम्स मेट्स पर 3.5-2.5 की कड़ी जीत के साथ सुनिश्चित हुई, जो उच्च-दांव दबाव में उनके साहस और रणनीति को रेखांकित करता है।

(ii) इससे पहले किसी भी भारतीय प्रायोजित टीम ने FIDE

वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप नहीं जीती थी। टीम MGD1 अंतरराष्ट्रीय टीमों के साथ कुलीन स्थिति में शामिल हो गई है, जिससे भारत की वैश्विक शतरंज साख में वृद्धि हुई है।

(iii) यह संस्करण व्यापक FIDE वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज़ टीम चैंपियनशिप का हिस्सा था, जो 10-16 जून को नोवोटेल लंदन वेस्ट में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में ग्रैंडमास्टर्स और एमेच्योर दोनों सहित शीर्ष वैश्विक प्रतिभाएँ शामिल थीं, जिसमें रैपिड इवेंट्स के लिए कुल पुरस्कार राशि €310,000 थी।

SUMMITS & CONFERENCE / COMMITTEES & MEETINGS

1. AYUSH मंत्रालय ने दिल्ली में 'योग कनेक्ट 2025' का आयोजन किया: "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" पर वैश्विक शिखर सम्मेलन।

14 जून 2025 को आयुष मंत्रालय ने दिल्ली के विज्ञान भवन में योग कनेक्ट 2025 नामक एक हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जो 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) से पहले एक प्रमुख कार्यक्रम था। "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" थीम पर केंद्रित इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य और स्थिरता में योग की भूमिका का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और चिकित्सकों को एक साथ लाया गया।

• इस शिखर सम्मेलन में 1,000 से अधिक लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, जिसमें बहरीन, अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों से बड़ी संख्या में वैश्विक दर्शक वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस कार्यक्रम का समन्वयन योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद (CCRYN) द्वारा किया गया था, ताकि अकादमिक, स्वास्थ्य और नीति-स्तरीय सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके।

• इस अवसर पर एक प्रमुख आकर्षण 'योग प्रभाव' रिपोर्ट का विमोचन था, जिसमें पिछले दशक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मापदंड, सार्वजनिक भागीदारी और अनुसंधान परिणाम शामिल हैं।

• ग्लोबल योग कनेक्ट 2025 शिखर सम्मेलन में भारत के योग और पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रयासों को उजागर करने के लिए तीन प्रमुख प्रकाशन लॉन्च किए गए। इनमें "योग का दशकीय प्रभाव" शामिल है, जो वैश्विक योग आउटरीच और इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों के दस वर्षों का सारांश देने वाली एक ई-बुक है; योग अनुसंधान का एक विज्ञानमितीय विश्लेषण, जो अकादमिक रुझानों में डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है; और "भारतीय वृक्ष वैभवम", स्वदेशी भारतीय पेड़ों के सांस्कृतिक और पर्यावरणीय मूल्य का जश्न मनाने वाला एक अनूठा कार्य है।

Key Points:-

(i) शिखर सम्मेलन में कई विषयगत सत्र आयोजित किए गए, जिनमें महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया, जैसे कि गैर-संचारी रोगों की रोकथाम में योग की भूमिका, सामान्य योग प्रोटोकॉल के प्रभाव का आकलन, योग-टेक के माध्यम से प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जीवन के विभिन्न चरणों में महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, तथा सार्वभौमिक योग अपनाने की वैश्विक क्षमता और आर्थिक मूल्य की खोज करना।

(ii) शिखर सम्मेलन में स्वामी बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, डॉ. एच.आर. नागेन्द्र, बिक्खु संघसेना और श्रीभारत भूषणजी जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं, जिन्होंने

दार्शनिक अंतर्दृष्टि और कल्याण संबंधी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।

(iii) योग कनेक्ट 2025 एक महत्वपूर्ण क्षण है - संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के दस साल बाद - और यूनेस्को द्वारा योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिए जाने को रेखांकित करता है। यह समग्र स्वास्थ्य, माइंडफुलनेस और वेलनेस डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करता है।

IMPORTANT DAYS

1. संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में कृत्रिम बुद्धि (AI) से प्रेरित खतरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए घृणास्पद भाषण के विरोध हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया।

हर साल 18 जून को दुनिया भर में नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित जागरूकता दिवस है। जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प A/RES/75/309 के माध्यम से स्थापित यह दिवस जून 2019 में शुरू की गई नफरत फैलाने वाले भाषणों पर संयुक्त राष्ट्र की रणनीति और कार्य योजना पर आधारित है।

• 2025 का थीम था "घृणास्पद भाषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संबंध: घृणा से मुक्त समावेशी और सुरक्षित वातावरण को पुनः प्राप्त करने के लिए गठबंधन का निर्माण।"

• इस वर्ष का फोकस AI-चालित घृणास्पद भाषण से निपटने पर था, जिसमें डीपफेक, एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और बॉट-जनरेटेड गलत सूचना द्वारा उत्पन्न चुनौतियां शामिल थीं।

Key Points:-

(i) संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने घृणास्पद भाषण को "शांति के लिए ज़हर" कहा, तथा जिम्मेदार प्रौद्योगिकी, मंच पारदर्शिता और वैश्विक सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

(ii) प्रमुख पहलों में नैतिक AI प्रथाएं, मीडिया साक्षरता अभियान, युवाओं के नेतृत्व वाले काउंटरस्पीच कार्यक्रम और वैश्विक #NoToHate सोशल मीडिया आंदोलन शामिल थे।

(iii) अफ्रीका, यूरोप और एशिया के देशों और संगठनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, शैक्षिक मंचों की मेजबानी की और ऑनलाइन और ऑफलाइन घृणास्पद कथाओं का मुकाबला करने के लिए मजबूत नीतिगत उपायों का आह्वान किया।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. चीन ने प्राकृतिक आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 'झांगहेंग1-02' उपग्रह लॉन्च किया।

14 जून 2025 को, चीन ने उत्तर-पश्चिम चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर विद्युत चुम्बकीय निगरानी उपग्रह झांगहेंग1-02 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इटली के सहयोग से तैयार किया गया यह उपग्रह भूगर्भीय और वायुमंडलीय जोखिमों पर नज़र रखने के लिए चीन के अंतरिक्ष-वायु-भूमि एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ाता है।

- **झांगहेंग1-02, जिसे CSES-02 (चीन सीस्मो-इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सैटेलाइट-02) के नाम से भी जाना जाता है, 6 साल की उम्र के साथ सूर्य-समकालिक कक्षा में संचालित होता है। यह नौ वैज्ञानिक पेलोड ले जाता है, जिसमें चीनी-इतालवी इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्टर और इटली से उच्च-ऊर्जा कण सेंसर शामिल हैं।**

- **यह उपग्रह वैश्विक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों, आयनमंडलीय स्थिति और तटस्थ वातावरण का अर्ध-वास्तविक समय में पता लगाता है। यह भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, चरम मौसम, बिजली और अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं के कारण होने वाले विचलन को पकड़ता है।**

- **झांगहेंग1-02 से प्राप्त डेटा वैज्ञानिकों को भूवैज्ञानिक घटनाओं के साथ भौतिक-क्षेत्र विसंगतियों को सहसंबंधित करने में सहायता करता है, जिससे भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट की भविष्यवाणी को बल मिलता है। यह चीन की पूर्व चेतावनी, जोखिम आकलन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को और बेहतर बनाता है।**

Key Points:-

(i) झांगहेंग1-01 (2018 में प्रक्षेपित) के साथ युग्मित, यह नया उपग्रह समकालिक अवलोकन को सक्षम बनाता है, क्षैतिज स्थानिक और लौकिक संकल्प में सुधार करता है - जिससे आयनमंडलीय और विद्युत चुम्बकीय व्यवधानों का अधिक सटीक मानचित्रण होता है।

(ii) संयुक्त मिशन पेलोड विकास, डेटा एक्सचेंज और अनुसंधान में चीन-इटली सहयोग को और मजबूत करता है। इतालवी वैज्ञानिकों ने इस मिशन की प्रशंसा एक मील के पत्थर के रूप में की, जो माटेओ रिक्की के ऐतिहासिक पूर्व-पश्चिम सांस्कृतिक आदान-प्रदान को दर्शाता है।

(iii) चीन के 581वें लॉन्ग मार्च प्रक्षेपण को चिह्नित करते हुए, यह उपग्रह बीजिंग की नागरिक-अंतरिक्ष रोडमैप के तहत लचीले बुनियादी ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देता है। यह वैश्विक आपदा प्रबंधन, बेल्ट एंड रोड भागीदारों का समर्थन करता है, और दूरसंचार और नेविगेशन नेटवर्क को सुरक्षित करता है, साथ ही भविष्य के उपग्रह समूह के लिए मंच तैयार करता है।

BOOKS & AUTHORS

1. न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने अपनी संस्मरण पुस्तक: ए डिफरेंट काइंड ऑफ पॉवर का विमोचन किया।

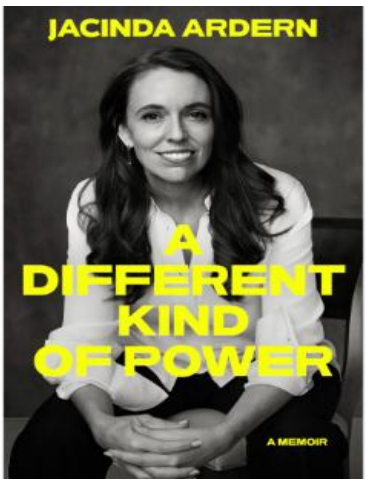

जून 2025 में, न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जैसिंडा केट लॉरेल अर्डर्न ने अपनी बहुप्रतीक्षित संस्मरण पुस्तक "ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर" जारी की। यह पुस्तक विरागो प्रेस (यू.के. स्थित लिटिल, ब्राउन बुक ग्रुप की एक छाप) और क्राउन पब्लिशिंग ग्रुप, पेंगुइन रैंडम हाउस (यू.एस.ए.) के एक प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है।

- **2017 से 2023 तक न्यूज़ीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री रहीं जैसिंडा अर्डर्न ने अपनी सहानुभूतिपूर्ण और समावेशी नेतृत्व शैली के लिए वैश्विक सुर्खियाँ बटोरीं। सिर्फ़ 37 साल**

की उम्र में, वह न्यूज़ीलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र की नेताओं में से एक बन गईं और पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म देने वाली दुनिया की दूसरी निर्वाचित सरकार प्रमुख बन गईं।

- **संस्मरण में आर्डर्न के शुरुआती राजनीतिक जीवन, प्रधानमंत्री पद तक उनके उत्थान और एक युवा महिला के रूप में विविधतापूर्ण गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाली चुनौतियों का एक चिंतनशील वर्णन है। वह 2017 में चुनाव के बाद की गहन बातचीत के दौरान अपनी गर्भावस्था का पता लगाने के बारे में खुलकर लिखती हैं।**

- **अर्डर्न ने 2019 क्राइस्टचर्च मस्जिद गोलीबारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बहुत ही मार्मिक अंतर्दृष्टि साझा की, जहाँ उनके दयालु व्यवहार ने वैश्विक प्रशंसा अर्जित की। उनके नेतृत्व के परिणामस्वरूप त्वरित और सख्त बंदूक नियंत्रण सुधार हुए, जिसने न्यूजीलैंड के आग्नेयास्त्र कानूनों को नया रूप दिया।**

Key Points:-

(i) एक अध्याय शून्य-कोविड रणनीति को समर्पित है, जिसमें विज्ञान-संचालित निर्णयों, आक्रामक सीमा प्रबंधन और सार्वजनिक विश्वास को प्राथमिकता दी गई है। उनके कार्यकाल के दौरान न्यूज़ीलैंड ने वैश्विक स्तर पर सबसे कम कोविड-19 मृत्यु दर दर्ज की।

(ii) दस व्यक्तिगत नेतृत्व सिद्धांतों के माध्यम से, अर्डर्न ने आधुनिक राजनीति में शक्ति के अर्थ को पुनः परिभाषित किया है - सहानुभूति, भेद्यता और प्रामाणिकता को कमजोरियों के रूप में नहीं बल्कि प्रभावी शासन के लिए परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है।

(iii) यह पुस्तक नेतृत्व में महिलाओं के सामने आने वाली वैश्विक जांच पर भी प्रकाश डालती है, और बताती है कि उन्होंने किस तरह आलोचनाओं का सामना धैर्य के साथ किया। उनके दृष्टिकोण ने लिंग, मीडिया जवाबदेही और समावेशी राजनीतिक विमर्श पर बहस को प्रेरित किया।

Static GK

Bihar	मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार	राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान
UNGA	अध्यक्ष: एनालेना बैरबॉक	मुख्यालय: न्यूयॉर्क
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
ICC	अध्यक्ष: जय शाह	मुख्यालय: दुबई
Sri Lanka	अध्यक्ष: अनुरा कुमारा दिसानायके	प्रधान मंत्री: हरिनी अमरसूर्या
China	राष्ट्रपति: शी जिनपिंग	राजधानी: बीजिंग
Maruti Suzuki India Limited	स्थापना: 1981, गुरुग्राम	मुख्यालय: नई दिल्ली
Ministry of AYUSH	कैबिनेट मंत्री: सर्बानंद सोनोवाल	मुख्यालय: नई दिल्ली
International Labour Organisation (ILO)	महानिदेशक (DG) : गिल्बर्ट एफ. होंगबो	मुख्यालय : जिनेवा, स्विटजरलैंड
the World Organisation for Animal Health (WOAH)	अध्यक्ष: डॉ. सुज़ाना पोम्बो	महानिदेशक: डॉ. इमैनुएल सौबेरान
Vietnam	प्रधान मंत्री: फाम मिन्ह चिन्ह	राजधानी: हनोई
Iran	आधिकारिक भाषा: फ़ारसी	राजधानी: तेहरान
FIDE	राष्ट्रपति: अर्कडी ड्वोर्कोविच	मुख्यालय: लॉज़ेन, स्विटज़रलैंड